

प्राक्कथन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत बनाई गई राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 दिनांक 5 जुलाई, 2004 से लागू कर दी गई है। ग्लोबल वित्तीय संकटों के बाद बदले हुए बृहद आर्थिक सन्दर्भों में संसद द्वारा एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2003 पारित किया गया और 28.05.2012 से इसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तदनुसार विविध राजकोषीय संकेतकों के लिए संशोधित लक्ष्य नियत किए गए। एफआरबीएम अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत नए नियम मई 2013 को अधिसूचित किए गए।

उक्त अधिनियम तथा नियमावली के संगत उपबंधों की अनुपालना में, केन्द्र सरकार के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगों के साथ वृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत, संसद की स्वीकृति के बिना अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार पर दायित्वों के निर्वहन में कोई विसामान्यता की अनुमति नहीं है। विसामान्यता की स्थिति में वित्त मंत्री को उन परिस्थितियों जिनमें ऐसी विसामान्यता की स्थिति उत्पन्न हुई है, को स्पष्ट करने हेतु संसद के दोनों सदनों के समक्ष वक्तव्य देना होगा; जिसमें इस बात को स्पष्ट करना होगा कि क्या इस प्रकार की विसामान्यता आवश्यक है और वास्तविक अथवा सम्भाव्य बजटीय परिणामों से सम्बन्धित है; साथ ही सरकार को प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा भी देना होता है।

आर्थिक विकास में 2010-11 से 2012-13 में 9 प्रतिशत से लेकर 4.5 प्रतिशत स्तर की नरमी के साथ ही एक आम सहमति थी कि राजकोषीय घाटे के लगातार उच्च स्तर पर बने रहने से कई तरह के वृहद आर्थिक असन्तुलन पैदा होते हैं और इस सम्बन्ध में तत्काल सुधारात्मक उपायों को अमल में लाए जाने की जरूरत है। तदनुसार छमाही उपचारात्मक उपायों के एक भाग के रूप में सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा सफलतापूर्वक कम किया और इसके साथ ही राजकोषीय समेकन का अपना एक मार्ग भी प्रशस्त किया। आगे वित्त वर्ष 2013-14 में सरकार राजकोषीय औचित्य तथा समेकन अपनी वचनबद्धता पर पूरी तरह से अडिग थी।

तथापि प्रतिकूल विदेशी वातावरण, घरेलू अवसंरचना दबावों और धीमे विकास तथा मुद्रास्फीति के दबाव जैसी विविध चुनौतियों के चलते राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया पर एक जोखिम बना हुआ है। पिछले दो वर्षों में विकास दर दो प्रतिशत से नीची रही है। धीमी अर्थव्यवस्था, बृहद आर्थिक स्थिति कर राजस्व के अपेक्षा से कम अर्जन के कारण सरकारी संसाधनों पर दबाव बना हुआ है। और इसी के साथ संसाधनों के अनुप्रयोग की विविध मांगें भी बनी हुई हैं। अर्थव्यवस्था में वृद्धि के पुनरुद्धार को सरकार द्वारा उच्चतर पूंजी व्यय की अपेक्षा है, जबकि प्रतिकूल बृहद-आर्थिक परिस्थितियों के कारण समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सामाजिक और कल्याणकारी क्षेत्रों में उच्चतर व्यय आवश्यक हो गया है।

आर्थिक समुत्थान के प्रारंभिक संकेतों की आशा में आम बजट 2014-15 पेश किया जा रहा है। निर्यातों और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से आशा का भाव और आर्थिक कार्यकलापों की गति पकड़ने की संभावना है। सरकार ने राजकोषीय समेकन के अधूरे कार्य के प्रति अपनी वचनबद्धता पुनःपुष्ट की है। 2014-15 का बजट नई एफआरबीएम व्यवस्था में निर्धारित वचनबद्धता पूरी करने की ओर ही कदम है। तथापि, राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटे के लक्ष्य हासिल करने के लिए खर्च करने की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यय मिश्रण की संरचना में सुधार करना जरूरी है। इसके लिए या तो प्रत्यक्ष सरकार द्वारा अथवा कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा उच्च पूंजी निर्माण हासिल करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन तरीके में परिवर्तन करने होंगे।

इस दस्तावेज में उपर्युक्त वर्णित तीन विवरण हैं जिनमें इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार पर दायित्वों के निर्वहन में विसामान्यता के आधारों को स्पष्ट किया गया है, इसलिए इन्हें उक्त सांविधिक अपेक्षाओं की अनुपालना में संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा गया है।

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण 2014-15

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

2004-05 सतत मूल्यों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की वृद्धि 2010-11 में 8.9 प्रतिशत से 2011-12 में गिरकर 6.7 प्रतिशत और गिरकर 2012-13 में 4.5 प्रतिशत हो गई। अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त गिरावट का कारण रहे घटकों में संरचनागत संकुचन अर्थात् परियोजनाओं में विलंब, पर्यावरण अनुमोदनों और भूमि अधिग्रहण में गत्यावरोध, उच्च मुद्रास्फीति और बाह्य असंतुलन ने योगदान दिया है। 2013-14 में स.घ.उ. में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि होकर मामूली सुधार हुआ था। पिछले दो वर्षों में 5 प्रतिशत से कम वृद्धि का चरण सेवाओं वृद्धि में आधुनिकीकरण और उद्योग में दीर्घकालीन गिरावट के कारण रहा है। स्थायी मानसून के चलते कृषि में उच्चतर वृद्धि और वित्तीय और व्यवसाय सेवाओं में सुदृढ़ वृद्धि 2013-14 में वृद्धि के साधारण उछाल में सहायक रही।

2013-14 में बृहद-आर्थिक स्थिरीकरण द्वारा उच्च मुद्रास्फीति और वृद्धि संवर्द्धन वाले मामलों को संतुलित करना था। इसमें 2013-14 की दूसरी तिमाही तक देखी गई रुपये के तीव्र अवमूल्यन द्वारा अस्थिर बाह्य स्थिति का समाधान करना भी शामिल था। निवेश स्तर को बढ़ाकर उच्चतर वृद्धि प्राप्त करते हुए भुगतान शेष स्थिति में कुछ हद तक सुधार किया गया है, और राजकोषीय समेकन सहित मूल्य स्थिरता 2014-15 में प्रमुख तरजीही क्षेत्रों में रहेगी। बाह्य स्थिति में जबरदस्त बदलाव (चालू खाता घाटे में 2012-13 में 4.7 प्रतिशत से 2013-14 में स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत तक की गिरावट और 2013-14 के उत्तरार्ध में रुपये के महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण के कारण) और राजकोषीय पक्ष में सुधार (स.घ.उ. अनुपात में राजकोषीय घाटा 2012-13 में स.घ.उ. का 4.9 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 4.5 प्रतिशत) ने बृहद-आर्थिक स्थिरीकरण के लिए शुभ संकेत दिए हैं। 2013-14 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति स्फीति को रोकने, मिली जुली विदेशी आर्थिक स्थिति का प्रबन्धन करते समय बढ़ोत्तरी बनाए रखने की अनिवार्यता द्वारा चालित होती थी। समग्र शीर्ष स्फीति में सुधार के साथ-साथ थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुसार 2012-13 तथा 2013-14 की पहली दो तिमाहियों में यहां मई 2013 में 25 आधार बिन्दुओं तक की कमी की गई है। वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के दौर में मौद्रिक सहजता जून 2013 में स्थिर हो गई थी। और तत्पश्चात् मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कठोर कर दी गई। पिछले वर्ष 7.35 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में शीर्ष डब्ल्यूपीआई स्फीति का औसत 5.98 प्रतिशत रहा। दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति विवरण 2014-15 (जून, 2014) में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, अन्य बातों के

साथ-साथ, नकदी समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत पुनः खरीद दर को 8 प्रतिशत बनाए रखा है।

स.घ.उ. वृद्धि

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2013-14 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (2004-05 के मूल्यों पर उपादान लागत पर स.घ.उ. के अनुसार)। 2013-14 में अर्थव्यवस्था की 5 प्रतिशत से कम वृद्धि मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट का परिणाम थी, जिसमें 2013-14 में 0.4 प्रतिशत का विकास हुआ और सेवा क्षेत्र के व्यापार, होटल, परिवहन और संचार खण्डों में कम वृद्धि का परिणाम है। सकारात्मक पक्ष में, क्षेत्र अर्थात् कृषि, बिजली, गैस और जलापूर्ति, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यवसाय सेवाओं में 2012-13 के मुकाबले में 2013-14 में अधिक दर से वृद्धि हुई है।

स.घ.उ. के तिमाही अनुमानों के अनुसार स.घ.उ. में 2013-14 की पहली तिमाही में 4.7 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 की दूसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ साधारण तेजी दर्ज की गई। यह 2013-14 की तीसरी और अंतिम तिमाही में प्रत्येक में गिरकर 4.6 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण में संकुचन, 2013-14 की दूसरी तिमाही को छोड़कर, सभी तिमाहियों में देखा गया, और यह चिंता का विषय बना हुआ है।

मांग पक्ष में, स्थिर बाजार मूल्यों (2004-05) पर स.घ.उ. 2012-13 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2013-14 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-14 के दौरान वास्तविकता में उपभोग व्यय, सकल नियत पूंजी निर्माण और निर्यात की वृद्धि क्रमशः 4.8 प्रतिशत, (-)0.1 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत रही। 2012-13 में इन घटकों में वृद्धि क्रमशः 5.0 प्रतिशत, 0.8 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत थी। सीएसओ द्वारा जारी किये गए प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्यों (निवेश दर) पर सघउ के अनुपात के रूप में सकल घरेलू पूंजी निर्माण 2011-12 में 35.5 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 34.8 प्रतिशत था, जबकि वर्तमान बाजार मूल्यों (बचत दर) पर स.घ.उ. के अनुपात के अनुसार सकल घरेलू बचतें 2011-12 में 31.3 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 में 30.1 प्रतिशत हो गई। यह गिरावट मुख्य रूप से निजी कॉरपोरेट क्षेत्र में बचतों की कमी द्वारा और भौतिक आस्तियों में परिवारों द्वारा बचतों के कारण है।

कृषि उत्पादन

2013 के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, देशभर में दीर्घावधि औसत (एलपीए) की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। तृतीय

अग्रिम अनुमानों (15.5.2014) के अनुसार, 2013-14 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 2012-13 (अंतिम अनुमान) में 257.13 मिलियन टन की तुलना में 264.38 मिलियन टन (चावल 106.29 मिलियन टन और गेहूँ 95.85 मिलियन टन) रहा। दालों का उत्पादन 19.57 मिलियन टन, गन्ने का 348.38 मिलियन टन, तिलहन का 32.41 मिलियन टन तथा कपास 170 कि. ग्रा. प्रत्येक की 36.50 मिलियन गाँठे होने का अनुमान लगाया गया है।

कृषि ऋण प्रवाह 2003-04 में ₹ 86,981 करोड़ और 2011-12 में ₹ 5,11,029 करोड़ की तुलना में 2012-13 में बढ़कर 6,07,375 करोड़ रुपये हो गया है। 2013-14 के लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य ₹ 7,00,000 करोड़ था, परंतु उपलब्धि लक्ष्य से बढ़कर ₹ 7,30,765 करोड़ की हुई।

कीमतेँ

दिसंबर, 2013 तथा जनवरी 2014 में वस्तुओं की कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तथा सब्जियों के मूल्य में तेजी से उछाल के कारण 2013-14 में हैडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 5.98 प्रतिशत तक कम हुई है। समग्र डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति (प्राथमिक खाद्य पदार्थों तथा विनिर्माण खाद्य उत्पादों सहित) बढ़ी रही और 2012-13 में 9.28 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में औसतन 9.43 प्रतिशत रही। मुख्य (खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पाद) मुद्रास्फीति अधिकतर उछाल पर रही और 2013-14 के दौरान 2.94 प्रतिशत कम हो गयी।

जबकि खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रही, इसके प्रेरक समय-समय पर बदलते रहे हैं। 2012-13 में, मुद्रास्फीति अनाजों, दालों, सब्जियों, अंडे, मांस और मछली, चीनी और खाद्य तेल आदि सहित खाद्य के सभी प्रमुख उपसमूहों हेतु समग्र में उच्च बनी रही। तथापि, 2013-14 में प्राथमिक योगदान में अनाज, सब्जियाँ और अण्डा, मांस और मछली शामिल हैं। नवम्बर, 2013 में 13.61 प्रतिशत के उच्च स्तर से मई, 2014 में खाद्य मुद्रास्फीति घट कर 9.6 प्रतिशत हो गयी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नई श्रृंखला (सीपीआई-एनएस) की अखिल भारतीय मुद्रास्फीति 2013-14 में 2012-13 में 10.21 प्रतिशत की तुलना में औसतन 9.49 प्रतिशत रही। सीपीआई-एनएस के अनुसार मुद्रास्फीति नवम्बर 2013 में 11.16 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम होकर मई, 2014 में 8.28 प्रतिशत हो गयी।

उद्योग और सेवाएं

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आआईपी) के अनुसार औद्योगिक उत्पादन 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0.1 प्रतिशत कम हुआ है। 2013-14 के दौरान गिरावट मुख्यतः खनन, पूंजीगत सामान और उपभोक्ता वस्तुओं में मंदी के कारण हुई। उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्र विनिर्माण में 2013-14 में पिछले वर्ष में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0.8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। पूंजीगत सामान क्षेत्र

का उत्पादन 2013-14 में पिछले वर्ष में 6.0 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 3.6 प्रतिशत कम हुआ है।

विनिर्माण में सुस्ती के अनेक कारण हैं। मुद्रास्फीति काबू में लाने की जरूरत से आवश्यक हुई नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ बड़ी परियोजनाओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों ने निवेशों पर असर डाला। सकल नियत पूंजी निर्माण की वृद्धि दर 2010-11 की पहली तिमाही के आसपास मंद रही है। खनन और पूंजीगत सामान क्षेत्र में नकारात्मक गिरावट, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की कम मांग के कारण समग्र विनिर्माण वृद्धि में गिरावट हुई है।

हाइडल स्रोतों से बिजली के उत्पादन में संतुलित वृद्धि के कारण समग्र बिजली उत्पादन में वृद्धि 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 4.0 प्रतिशत की तुलना में 6.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ढांचागत अवरोधों के कारण खनन क्षेत्र में समग्र औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है।

विदेशी क्षेत्र

2013-14 के दौरान 312.6 बिलियन अमरीकी डालर निर्यात हुआ था, जिसने 2012-13 में 300.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2013-14 के दौरान 450.1 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात हुआ था जो 2012-13 की संगत अवधि में 490.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 8.3 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। 2013-14 में कुल आयातों का पीओएल आयात 36.7 प्रतिशत था। 2013-14 के दौरान गैर पीओएल आयात 2012-13 में 326.7 बिलियन अमरीकी डालर की अपेक्षा 12.8 प्रतिशत कम था। ज्यादा निर्यात और कम आयात से 2013-14 में व्यापार घाटे में किरावट आ गई और वह 2012-13 में 190.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2013-14 में 137.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

बीओपी आधार पर 2013-14 में निर्यात और आयात का मूल्य क्रमशः 318.6 बिलियन अमरीकी डालर तथा 466.2 बिलियन अमरीकी डालर था जिससे 147.7 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा हुआ। 2013-14 में निवल अस्पष्ट आय 2012-13 में 107.5 बिलियन अमरीकी डालर से 7.2 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में 115.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गयी। निवल अस्पष्ट आय में वृद्धि के साथ व्यापार घाटे में गिरावट से 2013-14 में चालू खाता घाटा 2012-13 में 88.2 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत) से कम होकर 32.4 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत) हो गया। चालू खाता घाटा में कमी स्वर्ण जैसे अनावश्यक आयातों के लिए किए गए उपायों की सफलता का संकेत देती है। तथापि, निम्न पोर्टफोलियो अंतर्वाहों, ऋणों और व्यापार ऋण तथा अग्रिम राशियों की निवल अदायगी के कारण निवल पूंजीगत अंतर्वाह 2012-13 में 92.0 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2013-14 में 47.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। मार्च 2014 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 बिलियन अमरीकी डालर था,

जो मार्च, 2013 के अंत में 292.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 12.2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाता है। अगस्त 2013 में, विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 275.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

रुपए की दैनिक विनिमय दर अगस्त 2013 में प्रति अमरीकी डालर 68 रुपये के स्तर पर कम हो गयी (28 अगस्त, 2013 में प्रति डालर 68.36 रुपये। तथापि, यह 28 मार्च, 2014 में प्रति डालर 60.10 रुपये तक सुधर गयी जो सीएडी को नियंत्रित करने तथा पूंजीगत प्रवाहों को तेज करने तथा यूएस फ़ेडरल रिजर्व टैपर पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। 2013-14 में रुपए की वार्षिक औसत विनिमय दर 60.50 रुपए प्रति डालर थी।

मुद्रा बैंकिंग और पूंजी बाजार

भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 मई, 2013 को अपनी वार्षिक मौद्रिक नीति विवरण में शीर्ष मुद्रास्फीति की क्रमिक मंदी के चरण में वृद्धि की सहायता के लिए 7.50 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत तक और अधिक 25 बीपीएस की नीति रेपोदर में कमी की घोषणा की। मई 2013 के बाद में अमरीकी फ़ेडरल रिजर्व द्वारा मात्रात्मक सुखद (क्यूई) के कम होने की संभावना की आशंका ने पोर्टफोलियो के निवेश का बहिर्वाह तेज किया है। विदेशी घटनाक्रमों से अर्थव्यवस्था में जोखिमों को मान्यता देते हुए तथा उदीयमान वृद्धि मुद्रास्फीति गतिकी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जुलाई, 2013 की प्रथम तिमाही समीक्षा में मुख्य नीतिगत दरों को स्थिर रखा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सितम्बर, 2013 को मध्य तिमाही समीक्षा में विदेशी माहौल में सुधार का ध्यान रखते हुए तथा सीएडी को कम करने और इसके वित्तपोषण को आसान बनाने के लिए कार्यरत उपायों पर विचार करते हुए विनिमय बाजार दबावों से निपटने के लिए प्रारंभ किए गए आपवदिक नकदी उपायों की अंशशोधित वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ की। एमएसएफ दर 10.25 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत की गई तथा सीआरआर का न्यूनतम दैनिक अनुरक्षण 21 सितंबर, 2013 के प्रारंभिक पक्ष से 99 प्रतिशत की जरूरत से 95 प्रतिशत प्रभावी तक कम किया गया। तथापि, मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा रुपये के आंतरिक मूल्य के परिरक्षण में सहायता हेतु नाममात्र का स्थिरीकरण प्रदान करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रेपोदर 25 आधार बिंदु बढ़ा करके 7.5 प्रतिशत कर दी गई।

उदीयमान नकदी स्थिति पर विचार करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएफ दर 7 अक्टूबर, 2013 को 9.5 प्रतिशत से 9.00 प्रतिशत कर दी। 11 अक्टूबर, 2013 से प्रारंभ प्रत्येक शुक्रवार को परिवर्तनीय दर नीलामियों के जरिए बैंकिंग प्रणाली की 0.25 प्रतिशत निवल मांग और समयबद्ध देनदारियों (एनडीटीएल) के समतुल्य अधिसूचित राशि के लिए 7 दिन तथा 14 दिन की अवधि

की आवधिक रेपो के जरिए अतिरिक्त नकदी के प्रावधान की घोषणा की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने, 29 अक्टूबर, 2013 की द्वितीय तिमाही समीक्षा में एमएसएफ दर को 9.00 प्रतिशत से 8.75 प्रतिशत तक घटाने के साथ अंशशोधित कम न होने वाले आपवदिक उपायों को आगे बढ़ाया। म्यूचुअल फंड की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को सक्षम बनाने हेतु जुलाई, 2013 को संस्थापित म्यूचुअल फंड की स्पेशल रेपो विंडो भी बंद कर दी गई। इन संकेतों के साथ कि मुद्रास्फीति अगले महीनों में बढ़े रहने की संभावना है, मुख्य नीति रेपो दर 7.50 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत कर दी गई।

28 जनवरी, 2014 में मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा में, मुद्रास्फीति अपेक्षा को थामने तथा अवस्फीतिकारी पथ पर अर्थव्यवस्था के सुरक्षित ढंग से निर्धारित करने के लिए मुद्रास्फीति में उच्च जोखिम के कारण रेपो दर को 8 प्रतिशत और अधिक बढ़ाया गया था।

2013-14 के दौरान, वैश्विक रुझानों के अनुरूप, भारतीय पूंजी बाजार अमरीकी फ़ेडरल रिजर्व के मात्रात्मक सुलभ को कम करने, अक्टूबर, 2013 में अमरीकी संघीय सरकार की कामबंदी तथा यूक्रेन की घटनाओं के कारण बाजार अपेक्षा द्वारा प्रभावित हुआ था। तथापि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में पुनः विश्वास भरा है जो वर्ष 2013 के पिछले चार महीनों के दौरान सकरात्मक निवल एफआईआई निवेश में व्यक्त होता है, जिसने जून-अगस्त, 2013 के दौरान निवल बहिर्वाहों के पिछले रुझान को बदल दिया है। 2013-14 में, भारतीय बाजारों में कुल निवल एणआईआई निवेश 8.9 बिलियन अमरीकी डालर था। जनवरी-मई, 2014 के दौरान निवल एणआईआई निवेश 15.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा जबकि 2013 में 12.1 बिलियन अमरीकी डालर था। मई, 2014 में, 5.7 बिलियन अमरीकी डालर का निवल एफआईआई अंतर्वाह भारतीय बाजारों में देखे गए।

केन्द्र सरकार के वित्त साधन

संकट के बाद राजकोषीय सुदृढीकरण के दौर में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 को छोड़कर राजकोषीय घाटे के बजटीय स्तर का कड़ाई से पालन किया, जब राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत था, (बजट अनुमानों से 1.1 प्रतिशत बिन्दु अधिक था)। प्रतिकूल वृहद् - आर्थिक घटनाक्रम, विशेष कर 2011-12 और 2012-13 के दौरान मुद्रास्फीति का बढ़ा स्तर, जिसने सरकार को राजकोषीय सुधार पर और अधिक जोर देने के लिए मजबूर कर दिया, राजकोषीय घाटा 4.9 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया, जो 5.1 प्रतिशत के बजटीय स्तर से कम था और 2013-14 में (अनंतिम) 4.5 प्रतिशत था (4.8 प्रतिशत के बजटीय/लक्षित स्तर से कम था)।

विकास में, विशेषकर विनिर्माण में गिरावट और 2013-14 में वित्तीय बाजार में मन्द रुझान के परिणामस्वरूप बजटीय संग्रहण

और विनिवेश प्राप्तियां कमतर रही। 2013-14 के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2013-14 के बजट में परिकल्पित विकास की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। 2013-14 में सकल कर राजस्व वर्षानुवर्ष 9.9 प्रतिशत बढ़कर ₹ 11,38,882 करोड़ हो गया। वृद्धि का यह स्तर अप्रैल-दिसंबर 2012 में 15.0 प्रतिशत और ब.अ. 2013-14 में परिकल्पित विकास से कम है। बजट अनुमान के अनुपात के रूप में, 2013-14 में सकल कर राजस्व 92.1 प्रतिशत था। 2013-14 में कर-भिन्न राजस्व ₹ 1,99,233 करोड़ है, जो बजट अनुमान का 115.7 प्रतिशत था। ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में 2013-14 के दौरान महत्वपूर्ण कमी आयी, यह कमी मुख्यतः विनिवेश प्राप्तियों के कारण आयी क्योंकि 55,814 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था राशि के केवल ₹ 27,555 करोड़ की वसूली की गई।

व्यय के मोर्चे पर संशोधित अनुमान 2012-13 की तुलना में ब.अ. 2013-14 द्वारा परिकल्पित 16.3 प्रतिशत अंतर्निहित वर्षानुवर्ष वृद्धि की तुलना में 2013-14 में कुल व्यय में वृद्धि 10.94 प्रतिशत रही है। ब.अ. के अनुपात के रूप में, आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय 2013-14 में 103 प्रतिशत था। यह मुख्य सव्बिडियों पर उच्च व्यय के चलते रहा जो 2013-14 में ₹ 2,47,596 करोड़ (ब.अ.

का 112 प्रतिशत) रहा। महालेखा नियंत्रक के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, मुख्य सव्बिडियां स.घ.उ. का 2.2 प्रतिशत रही। यह 1.9 प्रतिशत की बजटीय व्यवस्था से अधिक था।

केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2013-14 (ब.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद का 6.9 प्रतिशत रहा जबकि 2012-13 (सं.अ.) में 7.4 प्रतिशत था।

संभावनाएं

वर्ष 2013-14 में कुछ सकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं जो कि वृहत आर्थिक स्थिरीकरण, चालू खाता घाटे में स.घ.उ. के 1.7 प्रतिशत गिरावट आने, बाह्य आर्थिक स्थिति में अति महत्वपूर्ण नाटकीय सुधार आया और अर्थव्यवस्था राजकोषीय विवेकपूर्ण पथ पर रही। तथापि, मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति, और कम किए जाने की आवश्यकता है। इस नीति का तत्काल कार्य विनिर्माण में वृद्धि दर बढ़ाने के लिए निवेश चक्र में तेजी लाना है। न्यून वैश्विक सुधार, विनिर्माण में कम सुधार, हाल के माहों में हुए सुधार के रुझानों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में बड़े उछालों के न होने से, वर्ष 2014-15 में, इस अर्थव्यवस्था से यह उम्मीद की जा सकती है कि वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि 5.4 से 5.9 प्रतिशत के दायरे में दर्ज की जा सकेगी।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-मार्च		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-मार्च	
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
संपदा क्षेत्र					
1.	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़)				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	9389 ¹ आर	10473 ^{अ.अनु.}	11.9 ¹ आर	11.5 ^{अ.अनु.}
	(ख) 2004-2005 के मूल्यों पर	5482 ¹ आर	5742 ^{अ.अनु.}	4.5 ¹ आर	4.7 ^{अ.अनु.}
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2004-05=100)	172.2	172.1	1.1	-0.1
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100) @	167.6	177.6	7.35	5.98
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:औद्योगिक कामगार (2001=100) (औसत)	215	236	10.44	9.68
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)	8392	9507	13.6	13.3
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात*				
	(क) ₹ करोड़	2669162	2714182	13.8	1.7
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	490737	450068	0.3	-8.3
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात *				
	(क) ₹ करोड़	1634319	1894182	11.5	15.9
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	300401	312610	-1.8	4.1
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)*	-190336	-137458	3.8	-27.8
9.	विदेशी मुद्रा भंडार				
	(क) ₹ करोड़	1588418	1828375	5.5	15.1
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	292046	304223	-0.8	4.2
10.	चालू लेखा शेष (मिलियन अमरीकी डालर में)	-88163	-32397	12.8	-63.3
सरकारी वित्त साधन #			₹ करोड़		1
1.	राजस्व प्राप्तियां	877613	1015279	16.8	15.7
2.	कर राजस्व (निवल)	740256	816046	17.5	10.2
3.	कर-भिन्न राजस्व	137357	199233	12.9	45.0
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	532754	548206	-3.6	2.9
5.	ऋणों की वसूली	16268	12502	-13.7	-23.1
6.	अन्य प्राप्तियां	25890	27555	43.1	6.4
7.	उधार और अन्य देनदारियां	490596	508149	-4.9	3.6
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	1410367	1563485	8.1	10.9
9.	आयोजना-भिन्न व्यय	996742	1110400	11.7	11.4
10.	राजस्व खाता	914301	1023047	12.6	11.9
	जिसमें:				
11.	ब्याज भुगतान	313169	377502	14.7	20.5
12.	पूंजी खाता	82441	87353	3.1	6.0
13.	आयोजना व्यय	413625	453085	0.3	9.5
	जिसमें:				
14.	राजस्व खाता	329208	352543	-1.4	7.1
15.	पूंजी खाता	84417	100542	7.3	19.1
16.	कुल व्यय (9+13)	1410367	1563485	8.1	10.9
17.	राजस्व व्यय (10+14)	1243509	1375590	8.5	10.6
18.	पूंजी व्यय (12+15)	166858	187895	5.2	12.6
19.	राजस्व घाटा (17-1)	365896	360311	-7.2	-1.5
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	490596	508149	-4.9	3.6
21.	प्राथमिक घाटा (20-11)	177427	130647	-26.9	-26.4

1आर: पहला संशोधित अनुमान

अ.अनु. अनंतिम अनुमान

@ 52 सप्ताह का औसत

* सीमाशुल्क आधार पर।

महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े।